

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 24/21

GCMS NO 2021/41

अपील संख्या - 25/21

GCMS NO 2021/38

1. मु०सुगनी बेवा परमा (मृतक)
 - 1/1. माया पुत्री सुगनी बेवा परमा
 - 1/2. मुस०द्रोपती पुत्री सुगनी बेवा परमा
 - 1/3. सूरज पुत्री सुगनी बेवा परमा

2. इमरत

3. गोपाल पुत्रान परमा

पिन्दू पुत्र श्यामलाल सभी जातियान माली निवासीयान मैगजीन कस्बा करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांट

बनाम

1. भगवती पुत्र कलुआराम
2. श्यामलाल पुत्र रघुनाथ जातियान कोली निवासीयान हाल खिडकिया बाहर करौली तहसील व जिला करौली
3. प्रेम सिंह पुत्र भौरया जाति कुहार निवासी होली खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली
4. नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार जाति महाजन निवासी होली खिडकिया करौली तहसील व जिला करौली
5. मुकेश गुर्जर
6. पत्ते गुर्जर
7. दिनेश गुर्जर पुत्रान फूल सिंह जातियान गुर्जर निवासी राजपुर तहसील व जिला करौली

रेस्पो०

(अपीले विरुद्ध मु०नं० 10/20 निर्णय व डिक्री दिनांक 17.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली)

अभिभाषक अपीला० श्री रामजीलाल अग्रवाल

अभिभाषक रेस्पो० श्री लियाकत अली

दिनांक 08.09.2025

निर्णय

प्रस्तुत दोनो अपीले अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 17.3.21 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली पेश की है ।

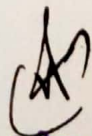
उक्त दोनो अपीलो के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांटगण द्वारा वाद पत्र इम्तनाई दवामी व हटाये जाने निर्माण इस आशय का पेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किया कि कस्बा करौली तहसील करौली में आराजी ख0न0 6311 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा पर वादीगण सन 1992 से लगातार वास्तविक कब्जे काशत करते चले आ रहे हैं। और आज तक कब्जे में है। तथा 3/4 हिस्से की हकूक खातेदारी है। तथा शेष 1/4 हिस्से की भूमि पर भी वादीगण का वास्तविक कब्जा बतौर मुशर्तका खातेदार ही है। शेष 1/4 हिस्से के संबंध में प्रेम पुत्र भौरया एवं हरिबाई बेवा भौरया जाति कुम्हार के जमाबंदी इन्द्राज रह जाने से नियत में बदनियती आ गई और वे वारविनाय वदयान्ती प्रतिवादीगण को अवैध रूप से हस्तान्तरण करने का प्रयास कर रहे हैं। जो स्ट्रेन्जर (अजनबी) है तथा उक्त अवैध हस्तान्तरण बताते हुए प्रतिवादीगण भूमि पर वादीगण के मुशर्तका कब्जे काशत पर व्यवधान डालने के लिए ऐलानिया धमकी दी रहे हैं। वादीगण निर्बल अनपढ़ कृषक हैं उनके धनबल व ताकत के आधार पर वगैर किसी अधिकारी के जमीन पर वादीगण के कब्जे में व्यवधान डालने से अपूर्णनीय क्षति है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी हैं। अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण व उसके परिजन व सहयोगीजन को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि विवादित भूमि खसरा न0 6311 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा वाके कस्बा करौली के सम्पूर्ण रकबे पर अथवा किसी भी भाग पर वादीगण के मुशर्तका कब्जे काशत में किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं पहुंचावे न ही अन्य किसी से पहुंचावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलाटगण द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने एवं काउन्टर क्लेम प्रतिवादी संख्या 3 डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी ख0न0 6311 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा कस्बा करौली के प्रतिवादी न0 3 व 6 के 1/4 हिस्से भूमि व शमूल चाह के कब्जा काशत में मदालखत मजाहमत नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह दोनो अपीले इस न्यायालय में पेश की गई है।

अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपीलो पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं दस्तावेजों का मूल्यांकन विधि अनुसार ना करके निर्णय व डिक्री पारित करने में भूल की है। जो निरस्त किये जाने योग्य है। आराजी ख0न0 6311 में राजस्व रिकार्ड के अनुसार 3/4 हिस्सा वादीगण का मानते हुए मुशर्तका कब्जा संयुक्त भाग से तय करने के उपरान्त भी वादीगण के हक में डिक्री पारित ना करने में कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजों साक्ष्य पर भरोसा ना करके जुबानी साक्ष्य पर भरोसा कर तनकी संख्या 2 अपीलांटगण/वादीगण के विरुद्ध तय करना न्यायहित में गलत है। इसलिए निर्णय व डिक्री अधिनस्थ न्यायालय निरस्त होने योग्य है। क्योंकि प्रतिवादी न0 3 प्रकरण हाजा में बतौर स्ट्रेन्जर है। इसलिए न्यायहित में जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से बंटवारा ना होने तक पाबंद किये जाने योग्य है।


राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

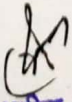
है। इसलिए जैर अपील निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 को तय करते समय पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड की अनदेखी करते हुए दावा वादीगण खारिज कर प्रतिवादी न0 3 ता 6 के 1/4 हिस्सा भूमि समूल चाह में मदालखत मजाहमत नहीं करने के लिए काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने में कानूनी भूल की है। क्योंकि राजस्व रिकार्ड में वादीगण का 3/4 व प्रतिवादी रेस्प0 का 1/4 हिस्सा प्रमाणित होने से कब्जा हर इंच पर प्रत्येक सहखातेदार का कब्जा होना कानूनी तौर पर मान्य होते हुए भी दावा वादीगण खारिज कर काउन्टर क्लेम प्रतिवादी डिक्री करने में कानूनी भूल की है। इसलिए निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। बयनामा 1/4 हिस्से के खातेदार काशतकार प्रेमसिंह, हरबाई पक्षकार बनाये गये हैं तथा फूल सिंह ने दौराने दावा नरेश पुत्र विनोद महाजन के विक्रय का दी है जो दावा होना में आवश्यक पक्षकार होने के कारण अपील में प्रभावी पक्षकार है और ताकत के बल पर जमीन विवादित को अपीलांट की कमजोरी का नाजायज फायदा उठाकर ताकत के बल पर अपील पर आमादा है और इनके हक में गैर कानूनी तरीके से काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने से अपीलांटगण को भारी आघात है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री व निर्णय एवं काउन्टर क्लेम निरस्त कर नरेश पुत्र विनोद महाजन को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से अजनबी व्यक्ति होने के कारण पाबंद कराने के अधिकारी है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर रेस्प0 संख्या 4 व 5 लगायत 7 के पिता फूल सिंह के हक में पारित काउन्टर क्लेम की डिक्री निरस्त फरमाई जावे तथा लॉकडाउन के समय को कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार फरमाई जावे।

रेस्प0 के अधिवक्ता न दौराने बहस कथन किया कि अपीलांट/वादीगण का कब्जा आराजी में व समूल चाह हिस्सा 3/4 में ही है जबकि आराजी के हिस्सा 1/4 व शमूल चाह के प्रारंभ से ही पूर्व खातेदारान प्रेमबाई व हरबाई प्रतिवादी न0 4 व 5 का निरन्तर चला आ रहा है और शांतिपूर्वक काशत करते चले आ रहे थे। प्रतिवादी न0 4 व 5 द्वारा अपना हिस्सा 1/4 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 30.3.07 को प्रतिवादी न0 3 को बिब ऐवज 151000/-रूपये में कर कब्जा प्रतिवादी न0 3 को संभलवा दिया है। जिसका सम्पूर्ण ज्ञान वादीगण/अपीलांटगण को रहा है। अपीलांट/वादीगण को कोई आपत्ति प्रतिवादी संख्या 3 से नहीं रही है। वक्त खरीद से ही प्रतिवादी न0 3 अपने 1/4 व समूल चाह पर शांतिपूर्वक काबिज रहकर काशत करता चला आ रहा है। खरीद के पश्चात ही आरंभित हिस्सा 1/4 की खातेदारी अधिकार प्रतिवादी न0 3 को प्राप्त हो चुके हैं। जिस पर आपत्ति करने का अपीलांट/वादीगण को कोई अधिकार नहीं है। वादीगण का हिस्सा 1/4 पर किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं रहा है तथा प्रतिवादी न0 4 व 5 द्वारा प्रतिवादी न0 3 को किये गये हस्तान्तरण का प्रारंभ से ही ज्ञान रहा है। वादीगण/अपीलांटगण को किसी प्रकार की कोई अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना नहीं है बल्कि वादीगण प्रतिवादी न0 3 के हिस्से 1/4 में मदालखत पैदा करने पर आमादा होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 5 ने बराबर हिस्सा राशि खर्च कर पुख्ता चाह का निर्माण कराया था जिसे प्रतिवादी संख्या 4 व 5 द्वारा घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विधिवत रूप से प्रतिफल प्राप्त कर आराजी में अपना

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

हिस्सा मय चाह को प्रतिवादी न0 3 को हस्तान्तरित किया गया है जिसकी जानकारी वादीगण को शुरू से ही थी। वादीगण/अपीलांट द्वारा प्रतिवादीगण को नाजायज रूप से परेशान करने एवं प्रतिवादी संख्या 3 को उसके कब्जे काश्त में मदालखत करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय में काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड एवं मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यो का विधिवत विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। अपीलांट/वादीगण अपने वाद पत्र को साबित करने में असफल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकी संख्या 1 को वादीगण के हिस्से 3/4 की हद तक सिद्ध माना है इसी प्रकार तनकी संख्या 2 ता 3 को प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट के पक्ष में साबित माना है। इससे सिद्ध है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड का अधिलोकन किये जाने के उपरान्त ही वादीगण का वाद पत्र खारिज कर प्रतिवादी संख्या 3 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर वादीगण को विधिवत रूप से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलाधीन निर्णय व अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन किया गया। जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 में विवादित आराजीयात ख0न0 6311 मु0सुगनी बेवा परमा व अमृतलाल,गोपाल पिसरान परमा हिस्सा 9/16, पिन्टू पुत्र श्यामलाल नाबा.संरक्षिका माता सूरजबाई बेवा श्यामलाल हिस्सा 3/16 जाति माजी सा. देह प्रेम पुत्र भौरया व हरबाई बेवा भोरया जाति कुम्हार सा.देह हिस्सा 1/4 दर्ज रिकार्ड है। खसरा न0 6311 सहखातेदार प्रेम.पुत्र भौरया व हरबाई बेवा भोरया द्वारा अपने हिस्से की 1/4 आराजी को फूल सिंह पुत्र कमल सिंह जाति गुर्जर निवासी होली खिडकिया करौली को विक्रय किये जाने से नामा0 संख्या 2608 दिनांक 19.4.07 के द्वारा फुल सिंह पुत्र कमल सिंह के नाम खातेदारी में दर्ज हुई है जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2060 से 2063 पटवार क्षेत्र करौली 9 में अंकित नोट से स्पष्ट है। खातेदार फूल सिंह पुत्र कमल सिंह द्वारा अपने हिस्से की क्य शुदा आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 27.6.13 को प्रतिवादी संख्या 3 नरेश पुत्र विनोद कुमार महाजन को विक्रय किये जाने से भूमि की खातेदारी जरिये नामा0 संख्या 3945 दिनांक 17.7.13 के द्वारा नरेश कुमार पुत्र विनोद कुमार महाजन के नाम स्वीकार हुआ है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2068 से 2071 में अंकित नोट से स्पष्ट है। चूंकि उक्त आराजीयात जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से हस्तान्तरित हुई है जिसके आधार पर ही क्रेता को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुए हैं। अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि अपीलांट की खातेदारी की आराजीयात पर प्रतिवादीगण धनबल एवं ताकत के बल पर व्यवधान डालने पर आमादा है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। इस तथ्य को साबित करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 2 कायम कर वादी/अपीलांट को साबित करने का भार निहित किया गया था। जिसके समर्थन में वादी द्वारा किसी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया बल्कि पी डब्लू सुगनी ने अपनी जिरह में अंतिम लाईन में स्वीकार किया है कि में



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमाफियाओ के संरक्षण मे प्रतिवादी संख्या 3 की जमीन हडपना चाहती हूँ। इस प्रकार अपीलांट इस तथ्य को अधिनस्थ न्यायालय मे सिद्ध नही कर पाये है ना ही अपील के माध्यम से उनके द्वारा ऐसा कोई ठोस दस्तावेज पेश किया है जिससे की यह साबित हो सके कि रेसपो/प्रतिवादीगण वादीगण/अपीलांट के कब्जे काशत मे व्यवधान पैदा करते हो। इस प्रकार वादी अपने वाद पत्र को साबित करने मे असफल रहने के कारण एवं प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम की स्वीकारोक्ति पी डब्लू सुगनी के अभिवचनो से होने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतःअपील खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली के प्रकरण संख्या 10/2020 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 17.3.2021 की प्रुटि की जाती है। निर्णय की प्रति दोनो पत्रावलियो मे पृथक पृथक संलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।




(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजेश्वर अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर